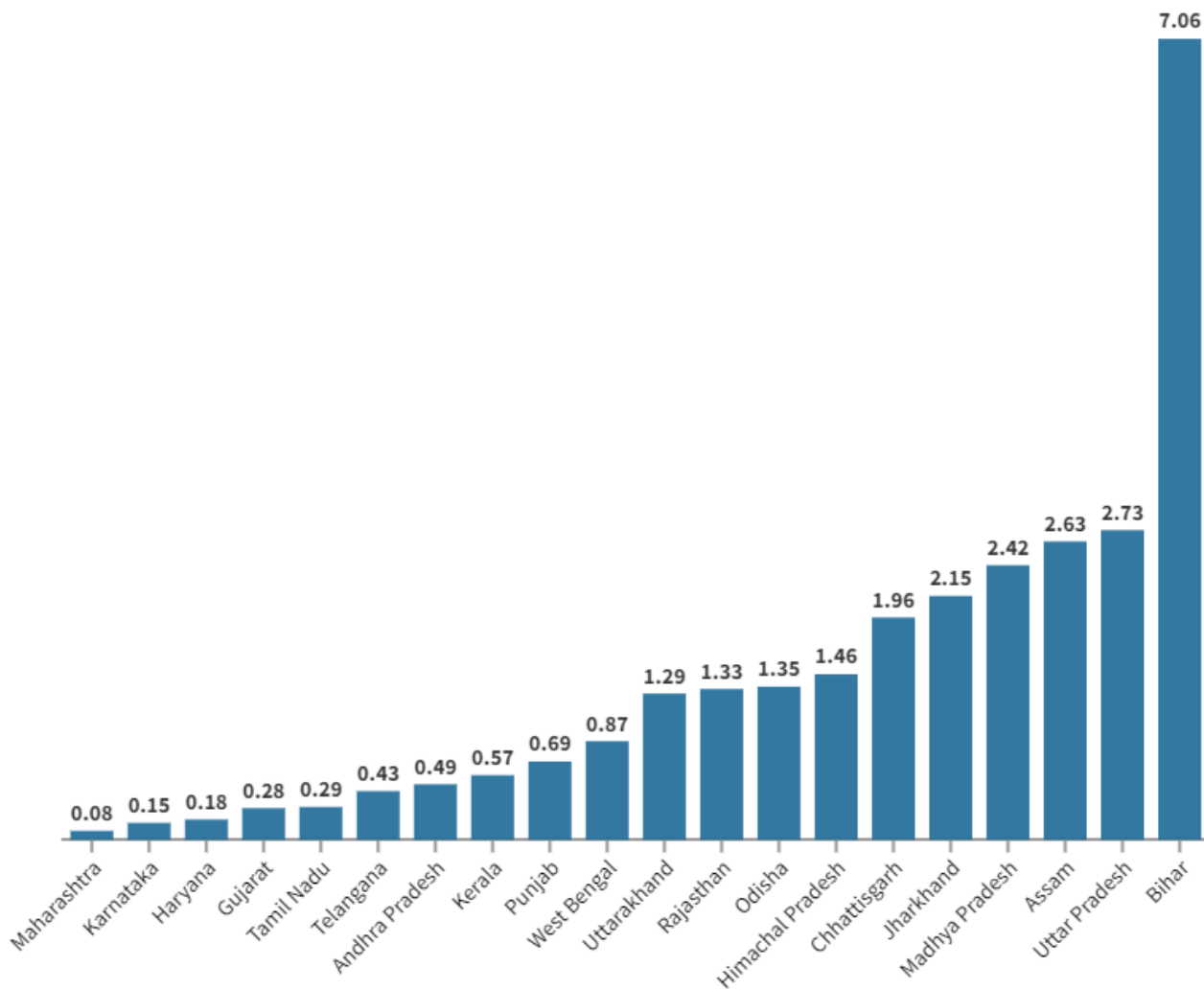


The amount in ₹ each State got for every rupee they contributed to Central taxes in 2021-22



//

15वाँ वित्त आयोग:

- परचय:
 - वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये विधिवि सूत्र निर्धारित करता है।
- संवैधानिकता:
 - संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वाँ वित्त आयोग:
 - 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था।
 - इसकी सफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।
 - सरकार ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हसिसेदारी को 41% तक बनाए रखने हेतु 15वें वित्त आयोग की सफारिश को स्वीकार कर लिया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत के 14वें वित्त आयोग की संसुतुतयिों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

स्रोत: द हद्दि

